

पुनर्जीवन अथवा गर्त की दिशा

पिछले वर्षों में बीएसएनएल बोर्ड एक के पश्चात दूसरा दो कन्सलटेंट्स, बीसीजी तथा डिलाइट्स, की नियुक्तियों की। इन दोनों कन्सलटेंट्स को ऐसे सुझाव देने थे जिससे कि कर्मचारी संसाधन तथा परफार्मेंस में सुधार हो। दोनों कन्सलटेंट्स ने अपने अपने सुझाव कम्पनी को दे दिए हैं। यह कितना हास्यास्पद है कि प्रथम निपुण कन्सलटेंट, बीसीजी की रिपोर्ट को ठंडें बस्ते में डाल दिया गया जबकि कम्पनी ने इसको भारी भुगतान भी किया है। आखिर बीसीजी की नियुक्ति का क्या अभिप्राय था तथा किन कारणों से अनावश्यक व्यय किया गया, विशेषतः उस समय जबकि कम्पनी की वित्तीय दशा भी चिंताजनक है। प्रबंधन ने इस संबंध में संघों से किसी भी प्रकार का विचार-विमर्श नहीं किया। कॉर्पोरेट कार्यालय के “रिस्ट्रक्चरिंग सेल” ने संघ से मन पसंद डिलाइट की सिफारिशों तथा सुझावों पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया था। संघ ने निर्धारित समय में उत्तर भी दिया। यह प्रसन्नता की बात है कि अनुभवी तथा निपुण अधिकारियों तथा मुख्य महाप्रबंधकों ने डिलाइट की कुछ विशेषतः कार्मिक सिफारिशों पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया तथा निगम की सेवाओं हेतु घातक एवं हानिकारक बताया। संघ ने स्पष्ट रूप से प्रबंधन को अवगत किया है कि वह पदों में कटौती तथा अधिकतम कर्मचारियों का काल्पनिक पदों के समायोजन प्रस्ताव के विरुद्ध है। संघ को पता चला है कि 26 फरवरी को तथा कथित विस्तृत चर्चा के उपरांत बोर्ड ने पुनर्जीवन योजना तथा कार्मिक योजना को अनुमोदित कर दिया है। डिलाइट कन्सलटेंट्स ने 26 फरवरी को सदस्यों के समक्ष सिफारिशों की प्रस्तुति दी तथा इसके पश्चात् डीओटी प्रतिनिधियों ने इसे पूर्ण रूपेण अनुमोदित करने का आदेश दिया। बीएसएनएल प्रबंधन समिति को केवल यह छूट है कि लाभ-हानि पर नजर रखें। कन्सलटेंट्स को कहा गया है कि वह सर्किलों के पुनर्गठन, गुणवत्ता में वृद्धि, नेटवर्क की आउटसोर्सिंग, रेवेन्यू में वृद्धि तथा ग्राहक संतुष्टी में वृद्धि आदि पर कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करें। **समय बताएगा कि यह मनमाना अनुमोदन उपक्रम को पुनर्जीवन सुनिश्चित करेगा अथवा गर्त की दिशा में भेजने में तीव्रता प्रदान करेगा।** कर्मचारियों का असंतोष एवं रोष का कम्पनी पर सुन्दर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संघ तथा कर्मचारी उपक्रम में स्टेक होल्डर्स है। परन्तु दुःखद है कि बोर्ड मनमाने ढंग से कार्यवाही की है। बोर्ड के जिन सरकारी प्रतिनिधियों ने अनुमोदन का दबाव डाला उनका कम्पनी की सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। परन्तु निगम में ज्ञानी, अनुभवी तथा दक्ष अधिकारियों की कमी नहीं है। वे भली भांति जानते हैं कि कम्पनी की क्या आवश्यकताएं हैं। आशा है वे समय की आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे तथा संघों से कार्मिक योजना तथा पुनर्जीवन योजना पर वार्तालाप सुनिश्चित करेंगे। जिससे कम्पनी के पुनर्जीवन प्रयास विफल नहीं हो। चर्चा हेतु नेशनल कौंसिल की बैठक उत्तम है। इसकी स्पेशल बैठक की आहुति पर सकारात्मक विचार आवश्यक है। कर्मचारियों के मध्य सकारात्मक सन्देश जाना चाहिए। कर्मचारी उत्सुक है कि उनकी जीविका, बीएसएनएल, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वे तत्पर हैं।